भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2327
07.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना के सामने आने वाली चुनौतियां

2327 डॉ. लक्ष्मी कान्त बाजपेयी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या पीएम ई-ड्राइव योजना को बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, और इन बाधाओं में, राजसहायता को हटाकर निजी इलेक्ट्रिक कारों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को बहिष्कृत करना, केवल सरकारी बसों को वित्तपोषित करना और बड़े निजी बस क्षेत्र की उपेक्षा करना, ईवी बैटरी के लिए आयातित सामान पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, विद्युत कनेक्शन मिलने में देरी के कारण ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में विलंब, ग्रामीण क्षेत्रों को नज़रअंदाज़ करते हुए अधिकांश चार्जिंग अवसंरचना शहरी क्षेत्र में होना, और अनिवार्य आधार-लिंक्ड ई-वाउचर प्रणाली के कारण ग्रामीण खरीदारों द्वारा दिक्कतों का सामना करना, शामिल हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना को प्रभावित करने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख): पीएम ई-ड्राइव स्कीम को प्रश्न में उल्लिखित बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

इस स्कीम को पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन, राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) को इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती हेतु अनुदान, ग्रामीण क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय आधार पर सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना तथा वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के माध्यम से देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तीव्रता से अपनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्कीम के दायरे एवं घटकों को सतत तथा समावेशी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

निजी क्षेत्र द्वारा संचालित निजी इलेक्ट्रिक कारों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों तथा बसों के लिए सहायता ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटक उद्योग (पीएलआई-ऑटो) हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सरकार ईवी मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीएलआई-ऑटो तथा पीएलआई-एसीसी स्कीमों सहित विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों, उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों तथा बैटरी पारितंत्र के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है।

देशभर में, ग्रामीण क्षेत्रों सहित, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायता भी अनुमोदित की गई है। लाभार्थियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने, दोहराव को रोकने तथा मांग प्रोत्साहनों के प्रत्यक्ष एवं प्रभावी संवितरण को सक्षम बनाने के लिए इस स्कीम का कार्यान्वयन आधार-आधारित ई-वाउचर सृजन सहित एक पारदर्शी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

****